available *to* the people. For the Government, to legislatively try and interfere with the rights as to what to broadcast and what not to broadcast, it may not be appropriate within our system.

LPG connections in the Country

† *105. SHRI DINA NATH MISHRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of LPG beneficiaries in the country, State-wise;

(b) the number of LPG connections which were added during the years of 1996-97, 1997-98, 1998-99 and 1999-2000;

(c) the additional number of those people who are expected to be given LPG connections during 2000- 2001; and

(d).by when the requirement of LPG is likely to be met in the country as per the assessment of his Ministry?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (d) A statement is laid on the tabic of the House.

Statement

(a) The total number of LPG (domestic) customer population registered with the distributors of Public Sector Oil Companies as on 1.4.2000 was 473.29 lakhs. The State-wise details arc given in the Table. *(See* below).

(b) LPG (domestic) enrolment in the country during the years 1996-97 to 1999-2000 is as under:

Year	Nos. in lakhs
1996-97	23.45
1997-98	41.39
1998-99	42.34
1999-2000	90.25

(c) and (d) Government have a plan to release one crore LPG (domestic) connections during the calendar year 2000 which will liquidate the waiting list registered with LPG distributors of Public Sector Oil Companies as on 1.12.1999.

† Original notice of ihe question was reveived in Hindi.

Table

Statewise Customer Population as of 1.4.2000

(Nos. in lakhs)

States	Total
Andhra Pradesh	43.16
Arunachal Pradesh	0.73
Assam	8.92
Bihar	13.14
Delhi	31.30
Goa	2.62
Gujarat	32.92
Haryana	16.49
Himachal Pradesh	7.62
Jammu & Kashmir	7.09
Karnataka	25.32
Kerala	16.91
Madhya Pradesh	22.34
Maharashtra	69.62
Manipur	1.11
Meghalaya	0.58
Mizoram	1.06
Nagaland	0.56
Orissa	5.83
Punjab	19.41
Rajasthan	17.80
Sikkim	0.37
Tamil Nadu	39.02
Tripura	1.22
Uttar Pradesh	57.24
West Bengal	26.32
State Total	468.72

States	Total
UNION TERRITORIES	
Andaman & Nicobar	0.19
Chandigarh	2.65
Dadra & Nagar Haveli	0.15
Daman & Diu	0.22
Lakshadweep	0.02
Pondicherry	1.35
Total	4.57
ALL INDIA	473.29

देश में एल.पी.जी. कनेक्शन

*105. **श्री दीनानाथ मिश्र**: क्या पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एल.पी.जी. लाभ भोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है,

(ख) वर्ष 1996-97,1997-98-99 और 1999-2000 के दौरान कितने कितने एल.पी.जी. कनेक्शन दिये गये,

(ग)2000-2001 के दौरान कितने और लोगों को एल.पी.जी. कनेक्शन दिये जाने की संभवाना है; और

(घ) उनके मंत्रालय के आकलन के अनुसार देश में एल.पी.जी. मांग को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां एल.पी.जी. (घरेलू) के पंजीकृत ग्राहकों की कुल संख्या 473.29 लाख है। राज्य-वार ब्यौरा तालिका में दिया गया है (**नीचे देखिए**)

(ख) वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान देश मे एल.पी.जी. (घरेलू) नामांकान निम्नानुसार है:

वर्ष	संख्या लाख में
1996-97	23.45
*1997-98	41.39
1998-99	42.34
1999-2000	90.25

(ग) और (घ) सरकार ने कैलेन्डर वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल.पी.जी. (घरेलू) कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है जिससे 1.12.99 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के यहां पंजीकृत प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी।

तालिका

1.4.2000 तक राज्यवार ग्राहक संख्या

(संख्या लाख में)

राज्य	योग
आन्ध्र प्रदेश	43.16
अरूणाचल प्रदेश	0.73
असम	8.92
बिहार	13.14
दिल्ली	31.30
गोवा	2.62
गुजरात	32.92
हरियाणा	16.49
हिमाचल प्रदेश	7.62
जम्मू और कशमीर	7.09
कर्नाटक	25.32
केरल	16.91
मध्य प्रदेश	22.34
महाराष्ट्र	69.62

राज्य	योग
मणिपुर	1.11
मेघालय	0.58
मिजोरम	1.6
नागालैण्ड	0.56
उड़ीसा	5.83
पंजाब	19.41
राजस्थान	17.80
सिक्किम	0.37
तमिलनाडु	39.02
त्रिपुरा	1.22
उत्तर प्रदेश	57.24
पश्चिम बगांल	26.32
राज्य योग	468.72
संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार	0.19
चंडीगढ़	2.65
दादर और नगर हवेली	0.15
दमन और दीव	0.22
लक्षद्वीप	0.02
पांडिचेरी	1.35
योग	4.57
अखिल भारत	473.29

श्री दीनानाथ मिश्र: सभापति जी, प्रश्न के उत्तर में इस साल जो एल.पी.जी. गैस कनेक्षन दिए गए हैं वे पिछले वर्षों के मुकाबले में तीन-चार गुना हैं। यह एक समाधान की बात मानी जा सकती है, लेकिन उसमें एक बात अस्पष्ट है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक वेटलिस्टिड जितने लोग हैं, उन सबको एल.पी.जी. कनेक्षन दे दिए जायेंगे। मै यह जानना चाहता

हूं कि यह आंकड़ा क्या है? कितने लोग वेट लिस्टिड हैं जिन्हें आपको इस वर्ष के अंत तक एल.पी.जी. कनेक्शन देने हैं.

मैं राज्यवार एल.पी.जी. कनेक्शन के आंकड़े देख रहा था तो उसमें उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश क एल.पी.जी. कनेक्शन लेने वालों की संख्या उपलब्ध लोगों की संख्या से बहुत कम है, अनुपात बहुत कम है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इसका प्रशासनिक कारण है या वहां के लोगों की क्षमता इसका कारण है?

श्री राम नाईक: सभापति जी, इस साल के अंत तक कितने हम गैस कनेक्शन देंगे इसके बारे में सी और डी में हमने लिखा है। 1 दिसम्बर, 1999 तक कुल मिलाकर 1 करोड़ की प्रतीक्षा सूची है और हम यह प्रतीक्षा सूची दिसम्बर 2000 तक पूरी करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता चला है कि जल्दी कनेक्शन मिल जाता है तो नयी प्रतीक्षा सूची उसमें ऐड हो रही है । इसलिए हम प्रयास करेंगे कि 1 दिसम्बर 99 को जो लोग प्रतीक्षा सूची में थे, जैसा मैने कहा कि वे एक करोड़ थे, उनको हम पहले पूरा करेंगे और उसके बाद जो नये आएंगे उनको भी कनेक्शन दिये देने का प्रयास करेंगे । यहां तक उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी के अनुपात में कम गैस कनेक्शन दिये गये हैं, अगर देश की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं, 69.62 लाख और दूसरा नम्बर उत्तर प्रदेश का जहां पर 67.24 लाख हैं। लेकिन यह बात सही है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्से और अर्बन सैंटर्स की इस प्रकार से तुलना करते हैं तो महाराष्ट्र में अर्बन सैंटर्स ज्यादा है इसलिए महाराष्ट्र की संख्या ज्यादा है। जो ग्रहक इसके आगे लेना चाहेगा, उसको भविष्य में देने का हमारा प्रयास है और उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं।

SHRIMATI VANG A GEETHA: I would like to know from the hon. Minister as to what is the number of applications pending so far out of the total applications for LPG agencies in Andhra Pradesh and I would also like to know whether the Government is going to provide any reservation for women in allotment of LPG agencies.

श्री राम नाईक: सभापति जी, हर राज्य में कितने पैडिंग हैं, उसकी सूची तो इस समय मेरे पास नहीं है, वह जानकारी में उनको दे दूंगा, लेकिन कहां कितने दिये हैं, उस सूची में तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद आन्ध्र प्रदेश का ही क्रमांक है जो कि 43.16 लाख है और आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने जो दीपम योजना चलाई है, उस दीपम योजना में जो गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको देने का प्रयास आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत सराहनीय कदम है और बाकी के राज्य भी इस तरह की योजना चलाएंगे तो उससे ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी के नीचे के लोग हैं, उनको गैस कनेक्शन का लाभ मिल सकता है। जहां तक गैस एजेंसीज देने का सवाल है, इस समय देश में 6,161 टोटल गैस एजेंसीज है। जिस गति से हम

नयी-नयी गैस कनेक्शन दे रहें हैं, उसके कारण हमने अभी 2,873 नयी गैस एजेंसीज़ देने के बारे में तय किया है। जो डीलर सलैक्शन बोर्ड भंग किये थे, उसके बदले में हमने नये बोडर्स बनाए हैं। उसके तहत अखबारों में विज्ञापन भी शुरू हो गया है। इसमें हमने यह तय किया है कि जो अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं जैसे स्वतंत्रता सैनानियों की है, मिलिट्री की है, अंपगों की है, शैड
यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स की है, इन सबमें हम महिलाओं को 33 परसेंट देने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि महिलाएं इसमें आगे आएं तो उनको इस बारे में प्राथमिकता देने का विचार हम करेंगे। पॉलिसी गाइड लाइंस के तौर पर डीलर सलैक्शन बोर्ड बने हैं, उनको हमने कहा है कि हर रिजर्वेशन में 33 परसेंट महिलाओं को देने का प्रयास करना चाहिए।

श्री मूल चन्द मीणाः महोदय, गैस एजेंसीज़ के जो डीलर हैं, वे गैस कनैक्शन के साथ-साथ घटिया किस्म के चूल्हे भी रखते हैं और गैस लेने वालों को जबर्दस्ती उन चूल्हों को बेचते हैं। एक तो यह देखने को मिलता है। दूसरा गैस एजेंसी के डीलर गैस सिलेंडरों से गैस निकाल लेते हैं। ये दो प्रकार की शिकायतें ज्यादा मिलती हैं। इन्हें रोकने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री राम नाईकः महोदय, जिन रूल्स के तहत डिसेट्रीब्यूटर को गैस एजेंसी दी जाती है, उसको भंग करने वाले दोनों उदाहरण आपने बताए। पहले ऐसा होता था कि पहले फर्स्ट वॉर्निंग, बाद में फाइन और उसके बाद में कैंसलेशन होता था। उन गाइडलाइन्स में हम लोग अब परिवर्तन कर रहें हैं। और सही शिकायत पहले समय में भी मिली है। यदि वह गंभीर होगी तो हम उनकी गैस एजेंसी समाप्त करने के बारे में भी एक गाइडलाइन्स बना रहे हैं और लगभग दो सप्ताह के अंदर वह गाइडलाइन्स तैयार हो जाएगी। जहां तक आपने बताया कि स्टोव लेने के लिए सख्ती की जाती है या गलत प्रकार के चूल्हे दिए जाते हैं, उसके बारे में हमने पोस्टर बनवाए हैं। वह भी आने वाले दस-पन्द्रह दिनों में हर एजेंसी में, हर भाषा में लगाए जाएंगे। यदि डिस्ट्रीब्यूटर किसी कारण होम डिलवरी नहीं करता है तो ग्राहक को उसे पांच रूपया वापस करने चाहिए। खराब चूल्हे लेने के लिए सख्ती नही होनी चाहिए, ऐसा भी उन पोस्टर्स में लिखा हुआ है। यदि कोई ऐसा करता है तो आप शिकायत करें। इस प्रकार के पोस्टर्स अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं में हमने बनवाएं हैं और हर गैस एजेंसी पर इनको लगाने का काम कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा।

श्री सभापतिः श्री संजय निरूपम....(**व्यवधान**)....

श्री मूल चन्द मीणाः गैस सिलेंडर में से जो गैस निकाली जाती है...

श्री राम नाईकः गैस सिलेंडर में से गैस निकालना है, सामान्यतः मुझे जरा यह मुशिकल लगता है और यह काम इतना आसान नहीं है लेकिन विज्ञान की प्रगति हो रही है। कुछ लोग करते भी होंगे क्योंकि एक दफा वह सिलेंडर ले जाने वाले के हाथ में गया तो....(**व्यवधान**).... मै यह बात मान

रहा हूं कि ऐसा हो सकता है लेकिन संभावना उसकी कम है। ऐसी बातों में स्पेसिफिक शिकायत, में यह नहीं कहता हूं कि आप वहां के रीजनल ऑफिस को ही करें, यदि आप मुझे भी लिख कर देते हैं तो मैं उस पर तुरंत कार्यवाही करूंगा, इतना विश्वास में आपको दिला सकता हूं।....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरोज दुबेः सभापति महोदय, चार दिन पहले हमारे यहां गैस सिलेंडर आया था और जब उसको तोलकर देखा गया तो उसके लगभग 10 किलो गैस कम थी। चार महीनें से बराबर हमारे यहां गैस आठ दिनों में ही खत्म हो जाती थी तो मुझे शक हुआ कि यह क्या मामला है? इस बार जब सिलेंडर आया है और हमने तुलवाया तो उसमें 10 किलो गैस कम थी। हमने उससे कहा कि तुम्हारी शिकायतें करेंगे, एफ.आई,आर करा देंगे तो वह बोला कि हमने समझा आपने कम किलो वाला सिलेंडर मंगाया है, अभी हम फुल किलो वाला लाकर दे देते हैं। यह राजहंस गैस सर्विस का मामला है और हम खुद गवाह हैं इस मामले के कि हमारे यहां गैस कम आई और यह हमने खुद देखा है। दो के तीन सिलेंडर हो जाना तो बहुत आसान काम है और हर जगह यह काम पेशेवर रूप में चल रहा है। इसके लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे क्योंकि इससे बहुत नुकसान होने वाला है। एक तो गैस वैसे ही इतनी मंहगी है और आठ दिन से ज्यादा वह चलती नहीं है, इसलिए इसके लिए आप सख्ती से कदम उठाएं।

श्री राम नाईकः जिस गैस एजेंसी का नाम आपने लिया है, मैं उसकी जांच कराऊंगा लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, वह एक ही साईज का है। आपके घर में दूसरे साईज का कोई सिलेंडर आया तो यह....(**व्यवधान**).....

श्रीमती सरोज दुबेः मंत्री जी, साईज नहीं... मंत्री जी, जो गैस सिलेंडर आता है, जो सप्लाई करता है, मैं उसकी बात कर रही हूं।

श्री राम नाईकः माननीय सदस्या की बात को मैंने मान लिया है और यह कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा।....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरोज दुबेः मंत्री जी, मैं बताऊं कि यह एम.पीज. के साथ....(**व्यवधान**).... यह एम.पीज. के साथ हो रहा है।.....(**व्यवधान**)....

श्री संजय निरूपमः अरे, एक ही सप्लीमेंटरी पूछिए। एक तो घुसपैठ की आपने।.... एक ही सप्लीमेंटरी पूछिए।....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरोज दुबेः यह एम.पीज. के साथ हो रहा है, आप इस बात पर गौर कीजिए। मंत्री जी, यह जो स्वर्ण जयन्ती सदन है जहां एम.पीज. रहते हैं.....(**व्यवधान**)....

श्री संजय निरूपमः यह तो एनक्रोचमेंट हो गया।... चेयरमैन साहब, इतना बड़ा अतिक्रमण हमारे समय के अंदर?....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबेः मंत्री जी पहले मेरी बात समझिए। स्वर्ण जयन्ती सदन जहां केवल एम.पीज. रहते हैं, अगर वहां सिलेंडर इतने कम तोल के आते हैं तो बाकी जगहों में क्या होता होगा? आप जरा इसको देखें और हमारे ऑब्जेक्शन करने के बाद वह सिलेंडर लेकर वापस भाग गया, यही बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह तो हम लोगों के साथ हो रहा है आम जनता की बात तो छोड़िए।

श्री राम नाईकः सभापति महोदय, यह बात तो सही है।.... आम जनता में फर्क करके गंभीरता में यह बात मत लीजिए। मेरे मुम्बई के घर में जब मेरी पत्नी किचन मे काम करती थी तो सिलेंडर एक महीना चलता था। मेरी पत्नी जब यहां आ गई लेकिन काम करने के लिए स्टाफ मिल गया है तो उस स्टाफ के जरिए अब सिलेंडर तीन सप्ताह मे ही खत्म हो जाता है। गैस सिलेंडर में गैस ठीक प्रकार से भरनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से जाते समय उसकी जांच होनी चाहिए। इस पर कड़ी निगरानी रखने की हम कोशिश करेंगे।

श्री संजय निरूपमः सभापति महोदय, हालांकि समय बहुत कम है। घरेलु गैस के वितरण का काम पहले सरकारी क्षेत्र में था लेकिन पिछले कुछ वर्षो से निजी कंपनियों के पास भी गया है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों में निजी कंपनियों को एल.पी.जी. सप्लाई करने की एजेंसी या अधिकार दिया गया है?

निजी कंपनियों के आने के बाद वेटिंग लिस्ट मेन्टेन करने का क्या अर्थ है? सरकार के पास पूरी तरह से कामकाज नहीं रहा है। एक जमाने में लोगों को बहुत किल्लत थी, बहुत ब्लैक मार्केटिंग होती थी। क्या निजी कंपनियों के आने के बाद आज भी कुछ राज्यों में एल.पी.जी.की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है?

श्री राम नाईकः इस समय सरकारी कंपनियों के जरिये एल.पी.जी. की जो सप्लाई होती है उसमें अभी भी सब्सिडी है। यह मार्च से है। गैस सिलेंडर में 130 रूपये की सब्सिडी है। जो निजी कंपनियां बेच रही हैं उन्हें उतने ग्राहक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये तुलना में सस्ते हैं। कुछ निजी कंपनियां तो बंद हो गई हैं और कुछ जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है अगर वे 2002 तक स्थिर हो गई तभी चलेंगी वरना अभी स्थिति यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की पी.एस.यूज. के जरिये जो गैस सप्लाई होती है वह कम कीमत होने के कारण अभी भी वेट लिस्टड है और मुझे लगता है यह रहेगी जब तक यह एक स्तर पर नहीं आती है। उसमें 2002 के बाद भी 15 परसेंट की सब्सिडी रखना तय है यह थोड़ा सा अंतर हो सकता है।

DR. DASARINARAYANA RAO: Sir, just now the hon. Minister referred to the Deepam Scheme which i.s going on in Andhra Pradesh. I would like to know as to how many connections have been given to Andhra Pradesh

Government till date. I would also like to know whether the Ministry has verified that the scheme has been properly distributed among the intended beneficiaries in Andhra Pradesh.

श्री राम नाईकः यह बंटवारा करने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार हमें यह कह रही है कि हमने इस प्रकार की योजना बनाई है, बहुत अच्छी योजना है इसमें केन्द्र सरकार के लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जितने एल.पी.जी. के सिलेंडर देते हैं उतना ही केरोसीन देने का कोटा कम हो जाता है। मुझे लगता है कि राज्यों में राज्य सरकारें यह काम ठीक प्रकार से कर रही है। एक जानकारी के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के लोग बताते हैं कि उनके यहां गरीब लोगों को भी सिलेंडर मिल रहा है इसलिए मोटे तौर पर यह ठीक प्रकार से चल रही है। अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो वे पहले राज्य सरकार के पास जाएं या हमें लिखें हम राज्य सरकार को बता देंगे।

श्री सभापतिः श्री वेद प्रकाश गोयल।

कुछ माननीय सदस्यः 12 बज गए। हाउस की घड़ी खराब है।

श्री सभापतिः अभी 11.58 हैं। आप बहुत देर से पहूंचे। यह बहुत देर की बंद हो चुकी है।

श्री लेखराज वचानीः माननीय सभापति जी....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः मैंने वेद प्रकाश गोयल जी को बुलाया है।

श्री लेखराज वचानीः नहीं हैं, नाम में कुछ मिस्टेक है।

सभापति जी, रूरल एरिये में एल.पी.जी. का लाभ पब्लिक को नहीं मिलता है। क्या सरकार सेक्रेट्री लेवल पर एल.पी.जी.की डीलरशिप देकर ग्रामीण पब्लिक को लाभ मिल सके, ऐसा कोई निर्णय करने का आश्वासन देगी?

श्री राम नाईकः सभापति जी, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम 2,873 नई गैस एजेंसियां देने वाले हैं। इनमें से 500 एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों को देने का एक नीतिगत निणर्य हमने लिया है। हर ब्लाक मे, कुछ जगहों पर तहसील भी कहते हैं, दोनों में जो बड़ा होगा वहां गैस एजेंसी देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उसके लिए मार्केटिंग सर्वे का आदेश हर ब्लाक स्तर पर दे दिया गया है। जैसे ही यह पूरा होगा हम हर ब्लाक स्तर पर नई गैस एजेंसी देने का निणर्य लेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.